युद्ध-ठंड की मार से मुक्ति की हो पहल

बिना लिहाज वाले रूस-यूक्रेन क्रूर युद्ध में दोनों तरफ बहुत ज्यादा जानी-माली नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना के सेना प्रमुखों के संयुक्त समूह अध्यक्ष जनरल मार्क ए मिले के अनुसार इस लड़ाई में लगभग 1 लाख रूसी या मारे गए या जख्मी हुए हैं और लगभग यही संख्या यूक्रेनी फौजियों की है, इसके अलावा लगभग 40000 आम यूक्रेनी नागरिक भी मारे गए और तकरीबन 1.5 से 3 करोड़ लोगों को बेघर होना पड़ा है।

जी. पार्थसारथी
लेखक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं।

सोवियत संघ के घटक रहे अधिकांश गणतंत्रों ने जहां रूस के साथ संबंध बढ़िया बनाए रखे, वहीं यूक्रेन को पिछले सालों में लगा कि उसे रूस के साथ रिश्ता निभाने में बदलाव लाकर, राजनीतिक और आर्थिक नीतिगत लचीलापन रखना चाहिए। युवा और करिश्माई राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के नेतृत्व में यही किया गया, और इस काम में बाइडेन प्रशासन ने तगड़ी सहायता की। सामरिक महत्व के क्रीमिया बंदरगाह तक अपने पहुंच मार्ग अबाध बनाये रखने और दक्षिणी यूक्रेन में बसे रूसी मूल के लोगों की सुनिश्चित भलाई के लिए जेलेंस्की के भावी यत्नों से पड़ने वाले व्यवधानों की आशंका से चिंतित हो उठे रूस ने यूक्रेन पर सैन्य चढ़ाई कर दी। इससे पहले, यूक्रेन की ओर से क्रीमिया स्थित अपने नौसैन्य अड्डे के पहुंच मार्गों को खतरा बनता पाकर रूस ने 18 मार्च, 2014 को सैन्य दखलअंदाजी कर समूचे इलाके पर अपना नियंत्रण बना लिया था, फिर भी क्रीमिया तक पहुंचती संचार लाइनों की सुरक्षा और दक्षिणी यूक्रेन अंचल में बसे रूसियों की सुरक्षा को लेकर उसकी चिंता बरकरार रही।

बिना लिहाज वाले रूस-यूक्रेन क्रूर युद्ध में दोनों तरफ बहुत ज्यादा जानी-माली नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना के सेना प्रमुखों के संयुक्त समूह अध्यक्ष जनरल मार्क ए मिले के अनुसार इस लड़ाई में लगभग 1 लाख रूसी या मारे गए या जख्मी हुए हैं और लगभग यही संख्या यूक्रेनी फौजियों की है, इसके अलावा लगभग 40000 आम यूक्रेनी नागरिक भी मारे गए और तकरीबन 1.5 से 3 करोड़ लोगों को बेघर होना पड़ा है। रक्त जमा देने वाली ठंड के बीच यूक्रेनी आक्रमण का जवाब देने में रूसी सैनिक किसी किस्म का लिहाज नहीं बरत रहे और मिसाइलों से यूक्रेन की बिजली आपूर्ति और संचार लाइनों को निशाना बना रहे हैं। रूसी हमलों से गैस आपूर्ति पहले ही कट जाने के कारण यूक्रेनियों की लगातार बढ़ती गिनती को घर-बार छोड़कर नई जगहों पर जाना पड़ा है, जिससे परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी भंग हो गई है। रूस से यूरोपियन देशों, जैसे कि जर्मनी की गैस आपूर्ति काट देने से नाटो संगठन के अन्य मुल्क भी मुश्किलों भरी ठंड का सामना करने का इंतजाम करने में लगे हैं।

स्पष्ट है यूक्रेन से रूस के दो महत्वपूर्ण हित जुड़े हैं। पहला, यूक्रेनी तट तक अबाध पहुंच मार्ग और दूसरा, दक्षिणी यूक्रेन में पीढ़ियों से बसे रूसी मूल के लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाए रखना। अमेरिका और नाटो सहयोगी देशों द्वारा प्रदत्त अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र से

लैस होकर यूक्रेन ने पहले दक्षिणी अंचल पर काबिज रूसी सेना को खदेड़ने के प्रयास शुरू किए थे। प्रत्युत्तर में रूस ने मिसाइल हमले करके यूक्रेन के गैस आपूर्ति एवं बिजली आपूर्ति तंत्र को तहस-नहस कर डाला, जिससे देशभर में और अधिक संख्या में यूक्रेनी नागरिकों को हड्डियां जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

यूक्रेन युद्ध ने यूरोप भर में भावनात्मक लहर पैदा कर दी है और उसके प्रति हमदर्दी उमड़ आई है। यूक्रेन में चल रहा घटनाक्रम लगातार अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बना हुआ है। भारत ने आरंभिक दिनों में तटस्थ रहना चुना, लेकिन शंघाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचा, जब उन्होंने एशिया भर के बड़े नेताओं सहित पुतिन और शी जिनपिंग की उपस्थिति में कहा 'आज का युग युद्ध करने का नहीं है और मैं आपसे इस पर विचार करने का आह्वान करता हूं। आज हमें यह मौका मिला है कि शांति के पथ पर कैसे आगे बढ़ें।' जहां जर्मनी और यूके सहित अधिकांश नाटो सहयोगी देश यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता में योगदान कर रहे हैं वहीं फ्रांसिसी राष्ट्रपति मैक्रॉन यूक्रेन शांति बहाली के लिए अर्थपूर्ण वार्ता करने के पक्षधर हैं। मोटे तौर पर यह वही रुख है जो भारत और चीन ने अपनाया है। इंडोनेशिया में हुई हालिया जी-20 बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शांति की अपील को पूरा समर्थन मिला है।

ठंड शुरू होने से यूरोप भर में प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ रही है। जाहिर है समूचे क्षेत्र में जमा देने वाली ठंड में ठिठुरते लोगों का गुस्सा बढ़ना तय है। जहां राष्ट्रपति पुतिन को आखिरकार यूक्रेन से वार्ता का स्वागत करना ही पड़ेगा, वहीं उनका मुख्य ध्यान क्रीमिया और ओडेशा बंदरगाह के पहुंच मार्गों पर बना रहेगा। पूर्व सोवियत संघ के दिनों में भी ओडेशा भारत सहित बाकी दुनिया से रूसी व्यापार का आयात-निर्यात केंद्र रहा है। रूसी तेल की कीमत को 60 डॉलर प्रति बैरल तक सीमित करने के अमेरिका के कड़े प्रयत्नों का सामना करने की तैयारी में दुनिया जुटी है। इस स्थिति से कैसे निपटेंगे, यह देखना बाकी है। जैसा कि अनुमान था, जी-20 की बैठक में पश्चिमी देशों ने रूस की कड़ी निंदा करना चुना, वहीं चीन और भारत को यकीन है कि इस किस्म की आलोचनाओं से रूस अपनी राह चलने से नहीं रुकेगा। इसलिए जरूरी है कि रूस और यूक्रेन बढ़ती जा रही चुनौतियों से निपटने को मिल-बैठकर यथार्थवादी नीतियां अपनाएं।

उधर, पाकिस्तान ने यूक्रेन त्रासदी में अपनाई नीतियों से दुनिया को चौंका दिया है। अधिकांश विकासशील देशों ने रूस और यूक्रेन को लेकर तटस्थ रुख अपनाए रखा, हालांकि कुछेक ने रूसी आक्रमण को लेकर असहमति जताई है।

पाकिस्तान ने पहले-पहल यूक्रेन पर रूसी चढ़ाई को लेकर चुप्पी साधे रखी। इसी तरह भारत, चीन और एशिया के कुछ मुल्कों ने भी बढ़ते युद्ध पर कोई एकतरफा वक्तव्य देने से परहेज रखा। परंतु अधिकांश विश्व को हैरानी हुई जब खबरें आई कि ब्रिटिश वायुसेना के परिवहन हवाई जहाजों के जरिए यूक्रेन तक गोला-बारूद सहित युद्धक सामग्री पहुंचाने के वास्ते पाकिस्तान अपने हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान कर रहा है, जाहिर है अमेरिकी मदद से। इसके बाद अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर मूल्य के सैन्य उपकरण देने की घोषणा आई।

पक्का है कि यह पूरा हवाई अभियान पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा की देखरेख में चला, जिन्हें इसके बाद वाशिंगटन और लंदन यात्राओं में काफी अधिमान मिला। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके तुरंत बाद मास्को पहुंचे पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने रूस से कच्चे तेल पर 30-40 फीसद रियायत देने की मांग की और संकेत दिए कि रूसियों ने इसको मंजूर कर भी लिया है। लेकिन हकीकत तब खुली जब पाकिस्तानी मीडिया ने रहस्योद्घाटन किया कि मास्को में मलिक की वार्ता बिना किसी ठोस निष्कर्ष के खत्म हुई। हालांकि रूसी पक्ष की ओर से मिली सूचनाओं में बताया गया है कि रूस ने रियायती दर पर तेल की पाकिस्तानी मांग पर विचार करने पर सहमति दे दी है और इस पर निर्णय राजनयिक माध्यम से बाद में बताया जाएगा।